(पाश की कविता)

तुम्हारे बगैर

तुम्हारे बगैर मैं बहुत खचाखच रहता हूं
यह दुनिया सारी धक्कमपेल सहित
बे–घर पाश की दहलीजें लांघकर आती–जाती है
तुम्हारे बगैर मैं पूरे का पूरा तूफान होता हूं
ज्वारभाटा और भूकंप होता हूं

तुम्हारे बगैर
मुझे रोज मिलने आते हैं आइन्सटाइन और लेनिन
मेरे साथ बहुत बातें करते हैं
जिनमें तुम्हारा बिल्कुल ही जिक्र नहीं होता
मसलन: समय एक ऐसा परिंदा है
जो गांव और तहसील के बीच उड़ता रहता है
और कभी नहीं थकता
सितारे जुल्फों में गूंथे जाते
या जुल्फें सितारों में–एक ही बात है
मसलन: आदमी का एक और नाम मेनशेविक है
और आदमी की असलियत हर सांस में बीच को खोजना है
लेकिन हाय–हाय!...
बीच का रास्ता कहीं नहीं होता
वैसे इन सारी बातों से तुम्हारा जिक्र गायब रहता है

तुम्हारे बगैर
मेरे पर्स में हमेशा ही हिटलर का चित्र परेड करता है
उस चित्र की पृष्ठभूमि में
अपने गांव की पूरे वीराने और बंजर की पटवार होती है
जिसमें मेरे द्वारा निक्की के ब्याह में गिरवी रखी जमीन के सिवा
बची जमीन भी सिर्फ जर्मनों के लिये होती है

तुम्हारे बगैर, मैं सिद्धार्थ नहीं–बुद्ध होता हूं
और अपना राहुल
जिसे कभी जन्म नहीं देना
कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी नहीं
एक भिक्षु होता है

तुम्हारे बगैर मेरे घर का फर्श–सेज नहीं
ईंटों का एक समाज होता है
तुम्हारे बगैर सरपंच और उसके गुर्गे
हमारी गुप्त डाक के भेदिए नहीं
श्रीमान् बी. डी. ओ. के कर्मचारी होते हैं
तुम्हारे बगैर अवतार सिंह संधू महज पाश
और पाश के सिवाय कुछ नहीं होता

तुम्हारे बगैर धरती का गुरुत्व
भुगत रही दुनिया की तकदीर होती है
या मेरे जिस्म को खरोंचकर गुजरते अ–हादसे
मेरा भविष्य होते है
लेकिन किंदर! जलता जीवन माथे लगता है
तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं।

पेज 1 का शेष भाग

उत्तराखंड की विनाशलीला मनुष्य-निर्मित

कैसे, राज्य से निकलने वाली नदियों पर 588 विद्युत परियोजनाओं के नाम पर पहाड़ों को थोथा किया जा रहा है और नदियों को विनाशकारी रूप से जलाश्यों में बदला जा रहा है। कैसे इंडिया-बुल नामक कारपोरेट ने कांग्रेस हाई कमांड को 400 करोड़ रुपये देकर विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाई जिसके बदले में उसे हज़ार-हज़ार मेगावट की दो विद्युत परियोजनायें बनाने की सौगात मिली। बहुगुणा का बेटा इन्डिया बुल में मुख्य कार्यकारी के पद पर है। कैसे, निशंक के चार साल के राज्यकाल में नदियों को अंधा-धुंध बांधने और पहाडों को बेतरह खोखला करने का काम सिरे चढाया गया, और जिसे खंडूरी ने जारी रखा।

याद रहे कि निशंक और खंडूरी दोनों भाजपाई मुख्यमंत्री थे; भाजपा नेतृत्व ने भ्रष्टाचार के आधार पर निशंक को हटाया था। पर खंडूरी भी बांध बांधने और पहाड़ों में सुरंग बनाने के रास्ते पर ही चलते रहे! भाजपा नेतृत्व भी खामोश रहा क्योंकि पार्टी फ़ंड को गर्म जो रखना होता है।

तभी बात-बात में केन्द्र की कांग्रेसी सरकार एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस्तीफ़ा मांगनेवाले तमाम भाजपाई नेता इस मुद्दे पर खामोश चल रहे हैं। किस मुंह से वे इस महाविनाश के असली कारणों तक जायें? जितनी कांग्रेस सरकारों की पोल खुलती है, उससे ज़्यादा उनकी अपनी सरकारों पर बात आयेगी। इस महा-विपदा की घड़ी में उनके अश्वमेधी सेनापति नरेंद्र मोदी की हुंकार भी इसी लिये सुनाई नहीं पड़ती।

वर्षों से प्रदेश के पैमाने पर व्यापक जनांदोलन उपरोक्त बांधों एवं सुरंगों के विरुद्ध चल रहा है। तमाम पर्यावरण विशेषज्ञों की इस अंधाधुंध मुनाफ़ा-दोहन के विरूद्ध चेतावनियां आती रही हैं। कैग की रिपोर्टों में भी आने वाले खतरों के प्रति सरकारी उदासीनता को रेखांकित किया गया है। सरकार की अपनी सूचना पहुंचाने वाली एजेंसियों ने भी रिपोर्टें दी ही होगी। क्या केन्द्रीय आपदा नियामक प्रधिकरण, जो इस मामले में सर्वोच्च संस्था है, के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले मनमोहन सिंह की आपराधिक लापरवाही में कोई कसर बाकी रह जाती है?

इस सारे दौर में हमारा तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया क्या कर रहा था? अखबारी भी और टी.वी. वाला भी? उन्हें भी उन्हीं कार्पोरेटों से विज्ञापन के बहाने मोटी रकमें चाहिये जो विनाशकारी विद्युत परियोजनाओं की मुनाफ़ाखोरी के जनक हैं। इन कार्पोरेटों में से कइयों का तो मीडिया के मालिकाना नियन्त्रण में हिस्सेदारी भी है। क्या इसे भी आपराधिक मिलीभगत नहीं कहा जाना चाहिये? क्या प्रेस परिषद के बड़बोले चेयरमैन जस्टिस काटजू अपना मुंह खोलना चाहेंगे?

सर्वोच्च न्यायालय भी केवल हेलिकॉप्टर भेजने तक की ही बात कर रहा है। क्योंकि बड़े कार्पोरेट की गर्दन नापना उसके बस की बात नहीं है। वैसे भी अदालत में बैठे जज को उतना ही दिखाई देता है जितना निहित स्वार्थ निभाने वाले वकील और पैरोकार उसे दिखाते हैं।

प्रथम-दृष्ट्या भी बहुगुणा, खंडूरी, निशंक और मनमोहन सिंह को जेल में पहुंचना ही चाहिये। उन पर हज़ारों मौतों अरबों-खरबों की सम्पत्ति के नुकसान एवं पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति के लिये एक विशेष जन-ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किया जाना चाहिये। इस ट्रिब्यूनल को अपनी सारी कार्यवाही 3 माह में पूरी करनी चाहिये। भारतीय दंड विधान के हिसाब से जो अधिकतम सजायें हैं, वे इन अपराधियों को मिलनी चाहिये। जांच एवं सुनवाई के दौरान जिन अन्य व्यक्तियों एवं कार्पोरेटों की आपराधिक सहकर्मिता पायी जाये, उन पर भी अलग से अगले 6 माह में दंड की प्रक्रिया पूरी की जाये।

अस्पताल में भी श्रम मन्त्री की नौटंकी ही

अपने चार साल के विधायक एवं मन्त्री-काल में शर्मा जी ने अपने अन्तर्गत आने वाली इस सेवा में रत्ती भर भी सुधार नहीं किया। इनका ध्यान तो केवल डाक्टरों व अन्य स्टाफ़ के तबादलों और नियुक्तियों पर ही रहा है। घटिया एवं ओछी सोच रखने वाले ये मन्त्री जी खरीदारी करने वाली पोस्टों पर उनकी नियुक्तियां करते हैं जो उनको कमीशन में से बराबर हिस्सा दें। जो हिस्सा न दे उसको जरा देर भी ये साहब टिकने न दें।

जिस दिन अस्पताल में यह नाटकबाजी इन्होंने की थी, उस दिन भी ये तत्कालीन एम एस आशा माथुर को यही संदेश देने आये थे कि उनका काम-काज ठीक नहीं है, इसलिये उनका यहां से तबादला किया जायेगा। वास्तव में जिस डा. माला बंसल को डा.माथुर की जगह अब लगा दिया गया है, उसे लगाने के लिये मन्त्री पर दबाव था। दबाव और किसी का नहीं उस मैट्रो अस्पताल का था जिसने पिछले दिनों मन्त्री जी की मु.फ़्त में एनजीओ प्लास्टी की थी। इसके अलावा डा. माला बंसल के पति यहां सिविल सर्जन रह चुकने के बाद हरियाणा ईएसआई चिकित्सा सेवा के निदेशक भी रह चुके हैं। इन पदों पर रह कर डा. बंसल ने मन्त्री जी की चोखी सेवा-पानी कर रखी है। और अब उनकी पत्नी से भी ऐसी ही सेवा की अपेक्षा तो की ही जा सकती है। लिहाजा नौटंकी ही सही।

मोदी और मनमोहन : असमान दिखते रोगी पर समान रूप से रोग हैं

दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों की ही सत्यनिष्ठा (इंटिग्रिटी) ज़ीरो है। यहां इतना स्पष्ट कर दें कि सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी दो अलग-अलग बातें होती हैं। मनमोहन सिंह की ईमानदारी की तो कांग्रेसी कसमें खाते हैं और मोदी पर भी बेइमानी का कोई सीधा आरोप अभी तक नहीं चिपक पाया है। पर जब बात सत्यनिष्ठा की आती है तो दोनों एक समान हैं।

प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक शपथ से बंधे होने के बावजूद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करते। इसके बाद भी वे कुर्सी नहीं छोड़ते, हालांकि उनसे बेहतर कौन जनता होगा कि वे दिन में चौबीसों घंटे, हफ्ते में सातो दिन साल में बरहो महीने, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ की उल्लंघना करते हैं। मन से, वचन से, कर्म से। अभी हाल में वे एक बार फ़िर आसाम से, झूठे रिहायशी पते के आधार पर, राज्य सभा के सदस्य चुने गये हैं। एक अकेले इसी आधर पर उनकी सत्यनिष्ठा ज़ीरो से भी नीचे आंकी जानी चाहिये।

मोदी की सत्यनिष्ठा के तो क्या ही कहने! क्रिकेट बोर्ड की सट्टेबाजी और उत्तराखंड की विनाश लीला पर वे यूं ही खामोश नहीं हैं। उनकी अपनी आपराधिक साझेदारी उन्हें चुप रहने की प्रेरणा देती है। गुजरात के 2002 मुस्लिम नर संहार में मोदी की भूमिका जग-जाहिर है। हत्याचार में लिप्त उनके करीबियों को जेल और मुकदमा झेलना पड़ रहा है। पर उनको इस दुर्दशा में लाने वाले मोदी की मौज-मस्ती एवं ठाठ-बाठ में कोई कमी नज़र नहीं आती। यदि उनमें सत्यनिष्ठा का एक अंश भी होता तो वे अपने इन साथियों एवं सहयोगियों के पक्ष में कोई राजनैतिक आंदोलन खड़ा करने की पहल तो करते। उनकी बला से बंजारों और कोदनानियों को भले फ़ांसी लगती है तो लग जाये। अन्दरखाने उन्होंने बेशक सभी को संदेश दे रखा है कि एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के रूप में ही उनका भला कर सकता है। पर चोरों में एक न एक दिन फूट तो पड़नी ही होती है। तब मोदी को सत्यनिष्ठा की कीमत भी चुकानी पड़ेगी।

सत्यनिष्ठा के अवसान की कीमत तो एक दिन मनमोहन सिंह को भी चुकानी पड़ेगी। आखिर रेत में गर्दन डालने वाला प्राणी शतुरमुर्ग भी एक दिन दुनिया देखता ही है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है उसके लिये।

मोदी और मनमोहन की समानतायें एक समान रूप से देश को खाये जा रही हैं।

हमारे काम के नहीं, तो गांव में क्यों रहे?

क्या-क्या शर्तें माननी पड़ी होंगी सिर्फ इसलिये कि बड़ी जाति के लोग उन्हें बस जिंदा रहने दें।

कल रात को इस बस्ती से दिल्ली वापिस लौटते समय मुझे भारतीय संस्कृति, धर्म, संविधान जैसे शब्द मूंह चिढ़ा रहे थे। और मेरी आंखों के सामने अस्सी साल की बुजुर्ग महिला की तस्वीर थी जो अपनी कमीज उघाड़ कर अपने सीने पर मारी गयी लात की चोट दिखा रही थी। ■

लोकतांत्रिक राजतंत्र

पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी किताब 'इंडिया : ए पोर्ट्रेट' में भारतीय संसद के बारे में यह सनसनीखेज खुलासा किया है-

लोक सभा में 30 साल से कम उम्र के सांसद को सच पूछें तो बपौती में कुर्सी हासिल हुई है और 40 साल से कम उम्र वाले कुल 66 सांसदों में से दो तिहाई से अधिक पुश्तैनी सांसद हैं।

इतना ही नहीं, नयी लहर वाले इन विधिनिर्माताओं (सासदों)को राजनीति में अपने समकक्षों से एक दशक का शुद्ध लाभ मिला है, क्योंकि पारिवारिक राजनीति से लाभ उठाने वाले हर औसत सांसद की उम्र उन सांसदों से 10 साल कम है, जो कोई खास पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद सांसद बने हैं।

कांग्रेस के अंदर स्थिति कहीं अधिक विकट है-35 साल से कम उम्र का हर कांग्रेसी संसद सदस्य पुश्तैनी सांसद है। अगर यही रुझान कायम रहा तो सम्भव है कि भारतीय संसद का हर सदस्य केवल पुश्तैनी सांसद होगा और देश वापस वहीं पहुंच जायेगा, जहां से स्वाधीनता आन्दोलन के पहले यह चला था, जब देश में वंशानुगत राजा और राजकुमार शासन किया करते थे।

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे। कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।